ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-6* July- 2020
Innovation The Research Concept

बिहार के विकास में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का एक समीक्षात्मक अध्ययन

A Critical Study of Various Five-Year Plans In The Development of Bihar

Paper Submission: 12/07/2020, Date of Acceptance: 25/07/2020, Date of Publication: 26/07/2020

चेतन कुमार
रिसोर्स पर्सन,
वाणिज्य विभाग,
एल. एस. कॉलेज,
मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

सारांश

सन् 1947 में अंग्रेजो के औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने पर भारतीय अर्थव्यवस्था उस स्वच्छ पटल के समान नहीं थी, जिस पर नए सिरे से कुछ लिखा जा सकता था। वह तो विगत पिछड़ेपन के जड़भार से ग्रस्त थी और विकास–विषयक संभावनाओं की दृष्टि से उसके सामने अनेक बड़े अवरोध उपस्थित थे।अंग्रेजो ने जो अर्थव्यवस्था हमें सौंपी उस पर निष्क्रियता और जड़ता की भाड़ी छाप मौजूद थी। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पहले उसमें विकास की जो संभावनाएँ मौजूद थीं, वे भारत को इंग्लैंड का एक उपनिवेश बना दिए जाने के पफलस्वरूप समाप्त हो गयी। भारत की सभी समस्याओं का अध्ययन किया गया और विचार–विर्मश किया गया कि कैसे भारत को विकसित किया जाये, जो पूरी तरह र्जजर हो चुका था। उस समय यह महसुस किया गया कि ही अन्य समस्याओं का समाधन निकाला जा सकता है। इस दृष्टिकोण से मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। इस अवधि में क्या–कितनी प्रगति की है ? हमारी क्या उपलब्धियाँ रही हैं ? देश की वर्त्तमान स्थिति कैसी है ? इन सभी पंचवर्षीय योजना में विकास किस गति से हुआ ? प्रस्तुत अध्याय में हम इन्हीं से जुड़ी बातों का अध्ययन कर रहे हैं।

When the British were free from colonial rule in 1947, the Indian economy was not like a clean board on which something could be written afresh. She was suffering from the backwardness of past backwardness and had many big obstacles in terms of developmental possibilities. The economy which the British handed over to us had a strong impression of inaction and inertia. Before the establishment of the British rule, the possibilities of development in it were ended as India was made a colony of England. All the problems of India were studied and deliberated on how to develop India, which was completely lost. At that time it was felt that only other problems can be resolved. With this view, the Planning Commission was formed in March 1950. What progress has been made in this period? What are our achievements? What is the current state of the country? At what speed did the development take place in all these five-year plans? In the chapter presented, we are studying these related things.

मुख्य शब्द : पंचवर्षीय योजना, कृषि क्षेत्र, उद्योग, शिक्षा।
Five Year Plan, Agriculture Sector, Industry, Education.

प्रस्तावना

भारत के प्रथम प्रधनमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू बनाये गए। इनकी अगुवाई में भारत की सभी समस्याओं का अध्ययन किया गया और विचार–विर्मश किया गया कि कैसे भारत को विकसित किया जाये, जो पूरी तरह र्जजर हो चुका था। उस समय यह महसुस किया गया कि. स्वतंत्रा भारत के सामने दो तरह की समस्याएँ थीं – लम्बे अरसे से चली आ रही पिछड़ेपन की समस्याएँ और द्वितीय विश्वयुद्ध तथा देश–विभाजन के कारण पैदा हुई तत्कालिक समस्याएँ। राष्ट्रीय सरकार ने सुनिश्चित एवं सुनियोजित ढ़ंग से इस वस्तु–स्थिति का सामना किया। 1951 से 1956 तक के लिए एक पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। उस योजना का प्रधन लक्ष्य था युद्ध और देश के विभाजन के कारण अर्थव्यवस्था में हुए असंतुलन को ठीक करना। इसके साथ ही साथ योजना का सर्वतोन्मुखी एवं संतुलित विकास की वह प्रक्रिया आरंभ

करानी थी जिससे राष्ट्रीय आय की वृद्धिऔर लोगों के जीवन स्तर में लगातार सुधर सुनिश्चित हो सके।

अध्ययन का उद्देश्य

सन् 1947 में भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिले । उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था निचले कड़ी पर थी भारत की आर्थिक सामाजिक शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में भी विकास के लिए पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया ।इन सभी पंचवर्षीय योजना में विकास किस गति से हुआ। प्रस्तुत लेख में अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य है।

भारत के विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)

1951 में भारतीय विकास के लिए योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूलमंत्रा यही रखा कि भारत एक कृषि प्रधन देश है। भारत की अध्कितम जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। इसे ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया। कृषि एवं सामुदायिक विकास में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सामुदायिक विकास पर सबसे अध्कि बल दिया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)

प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली इसकी सपफलता का आकलन करते हुए एक अप्रैल 1956 से द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सपफलता को देखते हुए देश की अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करने के लिए उससे भी अध्कि सशक्त योजना की आवश्यकता थी, जिसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया जिसके क्षेत्रा विस्तार स्वरूप उत्पादन, निवेश एवं रोजगार को सम्मिलित किया गया, जिससे विकास की गति को तीव्रतम रूप देते हुए देश की सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दुर करते हुए विकास किया जा सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे किसी भी क्षेत्रा को अछूता नहीं रख गया जिससे देश की आर्थिक विकास की गति अवरूद्ध हो। आर्थिक योजना अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती है अपितु भविष्य की योजना का एक ऐसा प्रारूप होती है, जिसपर चलकर आगे की शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हो सके। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना एक खास अवध्कि के लिए बनाई जाती है, जिसपर प्रयास करके उसके अच्छे परिणाम लम्बी अवध्कि तक प्राप्त होते रहे। इसका हर प्रयास एक नये विकास का मार्ग खोलता है और भविष्य में होने वाली समस्याओं के समाधन का प्रयास करता है। इसी दूरदर्शिता को ध्यान में रखकर एवं प्रथम पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया।

कृषि

प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए जितना अध्कि अन्न का उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं हो सका जिसके कारण द्वितीय योजना में भी कृषि के महत्व को कम नहीं रखा गया। यदि कृषि व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो देश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी जिससे हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। जिससे देश की अर्थ व्यवस्था में सुधर आयेगा। ऐसे देखा जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये गए उन कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि के क्षेत्रा में व्यापक परिवर्तन तो हुआ लेकिन जितना कृषि का विकास होना चाहिए था वह नहीं हो सका। इसका मूल कारण परंपरागत तरीके से कृषि करना, कृषि लागत अध्कि होना और उत्पादन कम होना था। जब सरकार को इस बात का एहसास हुआ, तो कृषि–शोध् कार्यक्रम को बढ़ावा हेतु अध्कि से अध्कि क्षेत्राो को सम्मिलित किया गया। इसके अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षित करना, खेती के नवीन तकनीक की जानकारी देना, नई तकनीकि उपलब्ध् कराना, उन्नत खाद एवं बीज मुहैया कराना, मिट्टी के अनुसार पफसल उपजाना, एक ही मिट्टी में एक से अध्कि पैदावार करना, ये सभी बातें शामिल थी।

उद्योग

आर्थिक नीति के अन्तर्गत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना को मूलतः औद्योगिक योजना मानकर उद्योग के विकास पर बल दिया। ग्रामीण क्षेत्राों में छोटे–छोटे उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया। 1952–53 में सरकार ने इस पर लगभग 1,052 लाख रूपये खर्च किये। तरह–तरह के कृषि उपकरण बनाये गये ताकि कृषि के उत्पादन में बढ़ोत्तरी होती जाये। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक सन् 1950–51 के आधर पर सन् 1960–61 में 164 हो गया। लौह तथा इस्पात, कोयला, उर्वरक, भारी इंजीनियरिंग के सामान और भारी बिजली के सामान के उद्योगों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। भिलाई, राऊरकेला और दुर्गापुर के तीन लौह इस्पात कारखाने, चितरंजन के रेल इंजन बनाने के कारखाने का विस्तार किया गया। रसायन उद्योग की प्रगति सराहनीय रही। खाद्य उद्योग के क्षेत्रा में भी आशातीत सपफलता प्राप्त हुई। इस योजना में कुछ सर्वथा नई वस्तुओं का उत्पादन देश में पहली बार प्रारंभ हुआ जिनका उत्पादन पहले नहीं किया जाता था।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66)

1 अप्रैल सन् 1961 से भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया गया और यह योजना 31 मार्च सन् 1966 को अपने जीवन के पाँच वर्ष पूरे कर समाप्त हो गई। इस योजना के विकास का कार्यक्रम निम्नांकित उद्देश्यों पर आधरित था :राष्ट्रीय आय में वृ(ि कृषि–उत्पादन में आत्मनिर्भरता, आधरभूत उद्योगो का विस्तार, देश के मानवीय शक्तियों का उपयोग और रोजगार अवसरों में वृ(ि अवसरों की समानता और आय तथा ध्न के वितरण की असमानताओं में कमी आदि।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–79)

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1 अप्रैल सन् 1966 से हो जाना चाहिए था, किन्तु अनिश्चित आर्थिक परिस्थितियों के कारण यह योजना लागू नहीं की जा सकी और तीन वर्षो तक एकवर्षीय योजनाए ही चलती रही। इस तरह चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1969 से लागू की गई।

उद्देश्य

चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थ–व्यवस्था को सक्रिय करना था। योजना प्रारूप के अनुसार इस योजना के आधरभूत उद्देश्य निम्नांकित थे।

1. समाज में अध्किाध्कि समानता लाना।

2. लोगों के रहन–सहन के स्तर में तीव्र गति से वृद्धिलाना।
3. सामाजिक न्याय की स्थापना करना।
4. राष्ट्रीय आय में 5.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धिकरना।
5. विदेशी)ण पर निर्भरता से मुक्ति प्राप्त करना।
6. कृषिगत उत्पादनों में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की स्थायी वृद्धिप्राप्त करना।
7. निर्यात में 7 प्रतिशत एवं अखाद्य सामग्रियों में 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धिलाना।
8. जनसंख्या वृद्धिको सीमित करना।
9. संतुलित क्षेत्रीय विकास करना तथा आर्थिक क्रियाओं का विकेन्द्रीकरण करना।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79)

पाँचवी पंचवर्षीय योजना की शुरूआत 1 अप्रैल सन् 1974 से की गई थी और 31 मार्च 1979 को अपने जीवन के पाँच वर्ष पूरा होने पर समाप्त होती परंतु कुछ कारणों से इसे 31 मार्च 1978 को ही समाप्त कर दिया गया।

उद्देश्य

इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था तथा इसके कुछ महत्त्वपूर्ण उद्देश्य जैसे निर्धनता उन्मूलन, रोजगार सुविधओं का विस्तार, न्यूनतम आवश्यक्ताओं की व्यवस्था, असमानताओं की कमी, जनसंख्या वृद्धिपर नियंत्राण, आत्मनिर्भरता आदि थे।

विकास की दर और स्वरूप

उपर्युक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पाँचवी पंचवर्षीय योजना की कार्यविधि में इन तत्वों का समावेश किया गया।

1. कुल घरेलु उत्पादन में 5.5 प्रतिशत की दर से वृद्धिहो।
2. उत्पादक रोजगार की संभावनाओं में विस्तार।
3. न्यूनतम आवश्यक्ताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसमें प्राथमिक शिक्षा, पीने के पानी की व्यवस्था, गाँवों में चिकित्सा के प्रबंध, पौष्टिक आहार, भूमिहीन श्रमिकों को मकान बनवाने की जमीन और गंदी बस्तियों का सपफाई व सुधर शामिल था।
4. समान से अधिक व्यापक कार्यक्रम।
5. खेती प्रमुख और बुनियादी उद्योगों तथा व्यापक खपत की चींजे बनाने वाले उद्योगों पर विशेष बल।
6. खपत की अनिवार्य वस्तुओं की निश्चित सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए सार्वजनिक रूप से इन वस्तुओं की प्राप्ति और वितरण की, कम से कम समाज के निर्धन लोगों के लिए उचित रूप से स्थिर दामों पर व्यवस्था।
7. निर्यात में तेजी से वृद्धिऔर आयात प्रतिस्थापन।
8. सामाजिक आर्थिक और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए संस्थागत, वित्तीय और अन्य उपाय।

छठवीं पंचवर्षीय योजना (1980–85)

छठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से शुरू की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्रा के लिए 1,72,210 करोड़ रूपये और निजी क्षेत्रा के लिए 74,710 करोड़ रूपये का प्रावधन किया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल विनियोग की राशि 1,85,710 करोड़ रूपये निर्धरित की गई। जिसमें से 8,49,000 करोड़ रूपये अर्थात् कुल विनियोग का 53 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रा में तथा 74,710 करोड़ रूपये अर्थात 47 प्रतिशत नीजी क्षेत्रा में व्यय किया गया।

उद्देश्य

इस योजना के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, जो निम्नलिखित थे – तीव्र आर्थिक विकास, गरीबी और बेरोजगारी में कमी, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, क्षेत्रीय असमानता में कमी, आय और सम्पत्ति की असमानता में कमी करना, लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहन आदि।

सातवीं पचंवर्षीय योजना (1985–90)

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक की अवधि में लागु थी। सातवीं योजना में 3,38,148 करोड़ रूपये का कुल परिव्यय रखा गया था। इसमें से 1,80,000 करोड़ रूपये का परिव्यय सार्वजनिक क्षेत्रा पर और शेष 1,68,148 करोड़ रूपये का परिव्यय निजी क्षेत्रा पर अनुमानित था। योजना आयोग के वर्तमान अनुमानों के अनुसार सातवीं योजना में सर्वजनिक क्षेत्रा का कुल वास्तविक परिव्यय 1984–85 कीमतो पर 1,78,377 करोड़ रूपये था।

उद्देश्य

भारत की सातवीं पंचवर्षीय योजना एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना थी। भारतीय योजनाओं के आधरभूत लक्ष्य वृ(, आधुनिकीकरण, आत्म निर्भरता तथा सामाजिक न्याय रहे हैं। इस ढ़ाँचे के भीतर ही सातवीं पंचवर्षीय योजना में तीन और जरूरी उद्देश्य रखे गए थे।

1. खाद्यान्न–उत्पादन की वृद्धि को बढ़ाना।
2. रोजगार के अवसर बढ़ाना।
3. उत्पादकता बढ़ाना।

सातवीं पचंवर्षीय योजना (1985–90)

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक की अवधि में लागु थी। सातवीं योजना में 3,38,148 करोड़ रूपये का कुल परिव्यय रखा गया था। इसमें से 1,80,000 करोड़ रूपये का परिव्यय सार्वजनिक क्षेत्रा पर और शेष 1,68,148 करोड़ रूपये का परिव्यय निजी क्षेत्रा पर अनुमानित था। योजना आयोग के वर्तमान अनुमानों के अनुसार सातवीं योजना में सर्वजनिक क्षेत्रा का कुल वास्तविक परिव्यय 1984–85 कीमतो पर 1,78,377 करोड़ रूपये था।

उद्देश्य

भारत की सातवीं पंचवर्षीय योजना एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना थी। भारतीय योजनाओं के आधरभूत लक्ष्य वृ(, आधुनिकीकरण, आत्म निर्भरता तथा सामाजिक न्याय रहे हैं। इस ढ़ाँचे के भीतर ही सातवीं पंचवर्षीय योजना में तीन और जरूरी उद्देश्य रखे गए थे।

1. खाद्यान्न–उत्पादन की वृद्धि को बढ़ाना।
2. रोजगार के अवसर बढ़ाना।
3. उत्पादकता बढ़ाना।

इन उद्देश्यों का गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असन्तुलनों की समस्याओं से गहरा संबंध है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)

आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक रहा। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्रा के लिए 4,34,100 करोड़ रूपये का परिव्यय अनुमानित किया गया था जो कुल निवेश (7,98,000द्ध का 45.2 प्रतिशत था। सार्वजनिक क्षेत्रा के परिव्यय के क्षेत्रावार निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं।

क्रम	मद	कुल परिव्यय	कुल का प्रतिशत
1	कृषि एवं संबंधित क्षेत्र	96,168.02	22.15
2	ऊर्जा	1,15,561.09	26.62
3	उद्योग एवं खनिज	46,921.75	10.81
4	परिवहन एवं संचार	81,035.55	18.67
5	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	4,131.71	0.95
6	सामाजिक सेवाएँ	79,011.90	18.20
7	अन्य	11,269.98	2.60
8	कुल	4,34,100.00	100.00

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में अन्य क्षेत्राो के महत्व के साथ–साथ ऊर्जा के क्षेत्रा को अध्कि प्राथमिकता दिया गया है।

नौवी पंचवर्षीय योजना (1997–2002)

नौंवी पंचवर्षीय योजना को भारत की स्वतंत्राता के 50 वे वर्ष में आरंभ किया गया था। यह योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक अवध्कि में लागू हुई। नौंवी पंचवर्षीय योजना में कुल निवेश 22,05,000 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें से सार्वजनिक क्षेत्रा का निवेश 8,59,200 करोड़ रूपये तथा निजी क्षेत्रा का निवेश 13,45,800 करोड़ रूपये था। इस योजना का लक्ष्य 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धिदर को प्राप्त करना था। यद्यपि नौंवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1999 से लागु की गई परन्तु इस योजना का विस्तृत प्रतिवेदन (Detailed Document) 19 फरवरी, 1999 को जारी किया गया।

उद्देश्य

भारत की नौंवी पंचवर्षीय योजना एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना थी। इस योजना के निर्माण तथा क्रियान्वयन में विशेष ध्यान रखा गया। नौंवी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे :

कृषि तथा ग्रामिण विकास को प्राथमिकता, मूल्यों में स्थिरता के साथ विकास, भोजन एवं पोषण सुरक्षा, उत्पादक रोजगार सृजन, आधरभूत न्यूनतम सेवाएँ, जनसंख्या वृद्धिदर को कम करना, पर्यावरणीय सुधर, सामाजिक आर्थिक परिवर्त्तन के एजेन्ट, जनता के सहयोग को प्रोत्साहन तथा आत्म निर्भरता।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007)

दसवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 2002 से 2007 तक की अवध्कि के दौरान औसतन आठ प्रतिशत प्रति वर्ष की सकल ध्रेलू उत्पादन विकास दर प्राप्त करना था। इसका उद्देश्य ग्यारहवीं योजना अवध्कि (2007–12द्ध के दौरान विकास दर में और तेजी लाने के लिए भी स्थितियाँ पैदा करना था। जिससे कि अगले दस वर्षो में देश की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो सके। निःसंदेह यह लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी था किन्तु दसवीं योजना का पूर्वानुमान इस प्रत्याशा पर लगाया गया है, कि देश में इन आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता है बशर्ते कि उपयुक्त नीतिगत उपाय और संस्थागत परिवर्तन तेजी के साथ और प्रभावी ढ़ंग से कार्यान्वित किए जाए।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012)

जब ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत की गई थी तब 2007–08 से 2011–12 तक की पाँच वर्ष की अवध्कि के लिए 9 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य निर्धरित किया गया था। ऐसी उम्मीद की गई थी कि विकास दर को योजना के समाप्ति वाले वर्ष तक 10 प्रतिशत पहुँचा दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य लक्ष्य विकास के प्रयासों में मूलभूत परिर्वतन लाना था, जिसके लिए अन्य 26 परिमेय सुचको की भी पहचान की गई थी। ये मुख्य रूप से गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं शिशु, बुनियादी सुविध एवं पर्यावरण से संबंध्ति है। इनके लिए विशेष लक्ष्य निर्धरित किए गए हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्रा के लिए नई प्राथमिकताएँ निर्धरित की गई थी। जब योजना की शुरूआत की गई थी तब विकास दर प्रतिवर्ष 7.7 प्रतिशत थी। तब विकास की और अध्कि पूर्णता की ओर बढ़ाते हुए और उसकी गति तेज करते हुए कई कमियों को पूर्ण रूप से खत्म करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी।

विभिन्न पंचवर्षिय योजनाओं का बिहार की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

पंचवर्षिय योजनओं के क्रियान्वयन के परिणाम के संदर्भ मं बिहार पर नजर डाली जाए तो हमें कई बदलाव स्पष्ट रूप से नगर आयेंगें। लेकिन कुछ क्षेत्रा ऐसे भी हैं जिन पर प्रभाव नगन्य है। विभिन्न क्षेत्राों में उपलब्धियाँ इस प्रकार है।

कृषि क्षेत्र

कृषि क्षेत्र पर यदि नजर डाली जाए तो इस क्षेत्रा में हमें काफी विकास देखने को मिलेगा। बिहार की अर्थव्यवस्था में परम्परागत रूप से ही कृषि की प्रधनता रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना मूलतः कृषि प्रधन योजना थी जिसका प्रभाव कृषि से संबंध्ति क्षेत्राों पर पड़ा। एक समय कृषि का क्षेत्रा ऐसा था, जब उपज कापफी कम होती थी। इसका मुख्य कारण उर्वरक, उन्नत किस्म के बीज एवं अन्य साध्नों की कमी। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान किसानों की आवश्यक सुविधएँ मुहैया कराई गई। उन्नत किस्म के बीज, उर्वरकों एवं सिंचाई के साध्न उपलब्ध कराए गए, साथ ही उन्हें कम ब्याज पर)ण की उपलब्ध्ता कराई गई तथा उन्हें कृषि के अत्याध्ुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके सिखाए गए। विभिन्न पंचवर्षिय योजना में कृषि का यंत्रीकरण पर अध्कि से अध्कि महत्व दिया गया। इन पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्रा में उल्लेखनीय उपलब्धि पफसल प(ति में आये परिवर्तन की है। जहाँ पहले पुरे वर्ष सिपर्फ एक पफसल उगाये जाते थे, वही अब एक पफसल के बदले दो या तीन पफसले उगाये जाते है। खरीपफ में धन और रबी के मौसम में गेहूँ उसी खेत में लगाने की क्रन्तिकारी प(ति इस शताब्दी की प्रगति का एक कीर्तिमान बन चुका है। जिससे इस राज्य

को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता करने का श्रेय पंचवर्षिय योजनाओं का ही है। देश की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अर्न्तगत बिहार में दो कृषि विश्वविद्यालय तीन कृषि महाविद्यालय एवं एक वानिकी विद्यालय की स्थापना हुई। इससे कृषि एवं इससे संबंध्ति क्षेत्राों में विकास को बढ़ावा मिला। इन सभी कार्यक्रमों के कारण लगातार तीन दशक तक खाद्यान्न के क्षेत्रा में रिकॉर्ड पैदावार किया। साथ ही साथ पफल सब्जियों एवं पफलों का भी उत्पादन वृहत पैमाने पर किया जाने लगा। पफलस्वरूप किसानों को कापफी प्रोत्साहन मिला। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि के क्षेत्रा में बिहार ने कई उपलब्ध्यिाँ हासिल की।

उद्योग : पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर डाली जाए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कापफी बड़े–बड़े औद्योगिक प्लान्ट इकाई की स्थापना हुई। इसी काल में लोक क्षेत्रा में स्थापित इस्पात उद्योग (बोकारो), भारी यंत्रा उद्योग (राँची), खाद (सिंदरी), तेल शोध्न (बरौनी), दव उद्योग (मुजफ्रपफरपुर)। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी वाहन, कृषि प्रोसेसिंग जैसे उद्योग स्थापित किए गए हैं। जिससे आरंभिक दौर में औद्योगिक विकास की रपफतार कापफी तेज कर दी।

परन्तु राज्य बॅटवारे के पफलस्वस्प राज्य की लगभग सारी वृहत इकाईयाँ झारखंड को चली गई। लघु एवं अतिलघु औद्योगिक इकाईयाँ बिहार के हिस्से में आयी। कापफी मात्राा में कच्चे माल का उत्पादन क्षेत्रा भी झारखंड में चला गया और मशीन यहाँ रह गई। तब यह कहावत चरितार्थ हुई ''कलम यहाँ, दवात वहाँ तो कैसे लेखन होई''।

बिहार के हिस्से आई कई छोटी औद्योगिक इकाईयाँ बंद पड़ी हैं और कुछ इकाई रूग्न अवस्था में है। जबकि कृषि आधरित इकाईयाँ नगन्य हो गई है। एक समय चीनी उद्योग बिहार का एक प्रमुख कृषि आधरित उद्योग था। इससे सहायक एवं संबंध्ति गतिविध्यिों के जरिए पाँच लाख किसानों और 50 हजार श्रमिकों की जीविका उद्योग पर निर्भर था। जहाँ राज्य में 1904 से 1940 के बीच जहाँ देश की 40 प्रतिशत चीनी का उत्पादन होता था। हालाकि अभी चीनी मिलों की संख्या 28 तक ही सीमित है जिसमें से 18 रूग्न है और शेष बंद पड़े हैं। अर्थात इन पंचवर्षीय योजनाओं से चीनी मिलों का विकास न होकर बल्कि धीरे–धीरे दम तोड़ती चली गई है। बिहार की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के निम्न स्तर मुख्य रूप से जिम्मेवारी निवेश संबंधी राजकीय नीतियों की है। जहाँ एक ओर अन्य सभी राज्यों में उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के अनुकुल नीतियों में संशोध्न किया गया वहीं राज्य में औद्योगिक निवेश आकर्षिक करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं हुआ। देश की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बावजूद भी बिहार में उद्योग का विकास नहीं हो सका।

अध्सिंरचात्मक नेटवर्क

सुदृढ़ प्रभवशाली एवं सुनियोजित अध्सिंरचनात्मक नेटवर्क किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का महत्वपूर्ण पहलु होता है। यदि बिहार के आधरभूत संरचना पर नजर डाली जाए तो ऐसा देखने को मिलता है कि आजादी के समय बिहार की स्थिति दयनीय थी। लेकिन विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के पफलस्वरूप राष्ट्रीय उच्च पथों तथा पुलों का निर्माण हुआ जो राज्य की विकास में कारगर साबित हुआ।

लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में अभी भी बिहार राज्य की इन्प्रफास्ट्रकचर निम्न स्तर के हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी तीन जिले ऐसे हैं जिनसे होकर राष्ट्रीय उच्च पथ नहीं गुजरती है। ये जिले हैं – जमुई, बांका और किशनगंज। आज भी सड़के पूर्ण रूप से हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती हैं। इसलिए सड़कों का निर्माण अभी भी बिहार की आवश्यकता है। राज्य में बुनियादी नेटवर्क का विकास न होने में पंचवर्षीय योजनाओं की विपफलता न होकर राज्य सरकार की नितीयाँ बहुत हदतक जिम्मेदार हैं।

सामाजिक असमानता में कमी

किसी भी राज्य का अधेतम विकास तभी संभव है जबकि समाज के सबसे निचली सीढ़ी पर बैठे लोग के समुचित विकास पर ध्यान दिया जाए। इन पंचवर्षिय योजनाओं में इस दिशा में सतत् प्रयत्नशील रहा है। इन योजना के अर्न्तगत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लोगों के कल्याण के लिए योजनाओं के माध्यम से, मुख्यतः शिक्षा, आर्थिक उन्नयन एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंध्ति योजनाओं के द्वारा असमानता की छाप मिटता गया है।

उपरोक्त अध्याय का अध्ययन करने के बाद हम कह सकते है कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव बिहार जैसे राज्य पर पड़ा। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्रा है जिनमें अभी भी हम विकसित राज्य के तुलना में पीछे हैं। इसलिए देश की अगामी पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्राों पर प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ताकि पिछड़े राज्यों का संतुलित विकास हो सके।

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्यों का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक तो यह कि आजादी मिलने के समय मौजूद कठिनाईयों और विकास के रास्ते में रूकावटों को बहुत–कुछ दूर कर लिया गया है। इस प्रकार विकास–प्रक्रिया को शुरू करना एवं उसे आगे बढ़ाना संभव हो गया है। दूसरे, उत्पादन के मौके पर हमारी उपलब्ध्यिाँ बहुत–कुछ संतोषप्रद ठहरती है। उत्पादन मात्राा और उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धिहुई है। चाहे हम उद्योग, कृषि या सेवा–क्षेत्रा में, देश ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। तीसरे कुछ विकास के बावजूद लोक–कल्याण को बढ़ाने में हम बहुत–कुछ विपफल रहे हैं। यदि हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वर्त्तमान स्थिति पर नजर डालें तो यह पहले की तुलना में कहीं बेहतर ठहरती है। यह पहले की भांति गतिहीन नहीं बल्कि गतिशील है, अब यह विकासोन्मुख है। यह विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसका स्पष्ट बोध् राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धिदर में होता है। इध्र आय की वृद्धिदर में तेजी नजर आने लगी है। संवृद्धिदर में बढ़ोत्तरी के अलावा देश की अर्थव्यवस्था का आधर मजबूत हुआ है, क्षमता बढ़ी है और इसमें पहले से कहीं अध्कि विविध्ता देखने को मिलती है। पुराने उद्योगों के विकास विस्तार के साथ–साथ अनेक नए उद्योग खुले हैं जिनमें कई उद्योग

विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ठहरते हैं जैसे कि इन्जीनियरी उद्योग, रासायनिक उद्योग आदि। आधरिक संरचना संबंधी सुविधओं का तेजी से विस्तार हुआ है। हरित क्रांति के आने से देश के कुछ प्रांतों में खेती के क्षेत्रा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस सब के पफलस्वरूप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन देश में होने लगा है। इसका विदेश व्यापार पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। इन अनेक बातों से स्पष्ट होता है कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्षो में संवृद्धि–दर में तेजी भी आई हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *भारतीय अर्थव्यवस्था, रूद्र दत्त, के.पी.एम. सुन्दरम*
2. *आर्थिक संवृद्धिऔर विकास, बी. सी. सिन्हा*
3. *बिहार की अर्थव्यवस्था, डॉ0 पी. सी सिन्हा*
4. *भारतीय अर्थव्यवस्था विकास एवं आयोजन, ए. एन. अग्रवाल*
5. *प्रतियोगिता दर्पण 2012 का विशेषांक*
6. *वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट*
7. *बिहार : टुवार्डस ए डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट*